जैक्सन तथा अमेरिकी प्रजातन्त्र

[JACKSON AND AMERICAN DEMOCRACY]

राष्ट्रपति के रूप में एण्ड्रयू जैक्सन का कार्यकाल, अमेरिकी लोकतन्त्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह उन लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियों का सच्चा प्रतिनिधि था, जो पिछले एक दशक से धीरे-धीरे आकार ग्रहण कर रही थीं। इस समय अमेरिकी समाज का कृषक और श्रमिक वर्ग यह अनुभव कर रहा था कि रिपब्लिकन दल और उसके पूंजीवादी समर्थक, उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। अतः वे ऐसी संघीय सरकार की स्थापना में अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करना चाहते थे, जो लोकतान्त्रिक मूल्यों की सच्ची प्रतिनिधि हो। इस प्रकार की सरकार ही उनके हितों की रक्षा कर सकती थी।

1820 के दशक से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ नई प्रवृत्तियां पनपने लगी थीं। अमेरिका भौगोलिक आधार पर स्पष्ट रूप से दो भागों—उत्तर और दक्षिण में विभाजित था। जहां तक आर्थिक हितों का प्रश्न है तो उत्तर और पूर्वी तथा दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के हित अलग-अलग थे। जहां उत्तरी राज्यों में औद्योगिक अर्थव्यवस्था, विकास के पथ पर अग्रसरित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर, दक्षिणी राज्यों में अर्थव्यवस्था मुख्यतः **'कृषि और उससे सम्बन्धित दास प्रणाली'** पर ही निर्भर थी। उत्तरी राज्यों के आर्थिक विकास के चलते, संघीय सरकार में भी उनका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ता था। यहां के लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत थे और यह चाहते थे कि दक्षिणी राज्यों में व्याप्त अमानवीय दास-प्रथा की समाप्ति हो, परन्तु दास प्रथा का प्रश्न, दक्षिणी राज्यों के आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ था, अतः वे किसी भी ऐसे प्रयत्न का पुरजोर विरोध करते थे। परिणामतः उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और इसने क्षेत्रीय संकीर्णता और विद्वेष का रूप ग्रहण कर लिया।

कई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों यथा, प्रशुल्क दर, बैंकिंग, मुद्रा, भू-राजस्व सम्बन्धी नीति, आदि पर भी अलग-अलग क्षेत्रीय राज्यों के भिन्न-भिन्न स्वार्थपरक मत थे। प्रत्येक क्षेत्र की जनता और पूंजीपति वर्ग यह चाहता था कि संघीय सरकार उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपनी आर्थिक नीति का निर्माण करे। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के आपसी वैमनस्य ने कई बार संघीय सरकार के समक्ष संकट भी खड़ा कर दिया। इसके चलते क्षेत्रीयता की भावना ने गलत रूप अख्तियार कर लिया।

अमेरिका के विभिन्न राज्यों की मतभिन्नता की एकमात्र सकारात्मक उपलब्धि यह रही कि इन राज्यों में कई योग्य राजनीतिज्ञों का पदार्पण हुआ। ये राजनीतिज्ञ, यद्यपि अपने-अपने क्षेत्रीय स्वार्थों से प्रेरित थे तथापि जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने में इन्होंने अपना पूर्ण योगदान किया। जब इन नेताओं के राजनीतिक ज्ञान ने एक उच्च स्थिति को प्राप्त किया, तो उनमें से कुछ नेताओं ने यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं की कि 'संघीय हित', क्षेत्रीय हितों से कहीं उच्च स्थान रखते हैं। यदि संघ पर कोई संकट विद्यमान हुआ, तो राज्य भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। इस विचारधारा के समर्थकों की कोई कमी नहीं थी। यह तथ्य, जनता की बढ़ती हुई राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक था।

अमेरिकी समाज के लिए यह एक ऐसे युग का आरम्भ था, जिसमें अभिजात्यवर्गीय श्रेष्ठता की भावना पर कई तरह से प्रहार हो रहे थे। यह प्रवृत्ति पश्चिमी राज्यों में विशेष रूप से विद्यमान थी। पश्चिमी राज्यों

की सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियां, कुलीनतन्त्रीय व्यवस्था के प्रतिकूल थीं। **यहां वह 'आर्थिक भेद' समाज में नहीं पाया जाता था, जो उत्तरी या दक्षिणी राज्यों में विद्यमान था।** यहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं था। अतः यहां 'सच्चे लोकतन्त्र' की स्थापना की काफी अच्छी सम्भावना थी। ऐसी ही बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सच्चा प्रतिनिधि एण्ड्रयू जैक्सन था।

अमेरिका में जो 'क्रान्ति' हुई थी, उसने जनता के अधिकारों में वृद्धि की और उन्हें अपने अधिकारों को लेकर सचेत भी किया था। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप मताधिकार को बढ़ाया गया। लोगों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया गया, परन्तु अभी आम जनता को वे अधिकार प्राप्त नहीं थे, जो समाज के अभिजात्य वर्ग को प्राप्त थे। **संघीय सरकार और प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर, अभिजात्यवर्गीय लोगों का ही एकाधिकार था।** वे जिन नीतियों का निर्माण करते थे, वे उनके वर्गीय हितों की ही पूर्ति करते थे। सामान्य जनता के हितों और आवश्यकताओं के प्रति वे पूर्णतः उदासीन थे, लेकिन बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के चलते आम जनता अपने शोषण के इस तरीके से परिचित हो रही थी। आम जनता यह समझने लगी थी कि वही सरकार, उनके हितों की रक्षा कर सकती है, जो उनके मतों के आधार पर चुनी गई हो।

उपर्युक्त परिस्थितियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अब अमेरिकी जनता को लोकतन्त्र की असली अवधारणा के विषय में ज्ञान होने लगा था। उन्हें आवश्यकता एक ऐसे नेता की थी, जो उनके बढ़ती हुई राजनीतिक जागरूकता, महत्वाकांक्षा और योजनाओं को एक निश्चित दिशा प्रदान कर सके। उनकी इस आकांक्षा की पूर्ति एण्ड्रयू जैक्सन ने की।

राष्ट्रपति के रूप में जैक्सन का चुनाव

19वीं सदी के दूसरे दशक से ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ योग्य और जागरूक राजनीतिज्ञों को यह लगने लगा था कि राष्ट्र में एकदलीय राजनीति कई अर्थों में घातक सिद्ध हो रही है। लोकतन्त्र का सही विकास उस परिस्थिति में सम्भव होता है जब राष्ट्र में दो राजनीतिक दलों, जो शक्ति और प्रभाव लगभग एकसमान हों, का अस्तित्व विद्यमान हो। **ऐसी विचारधारा रखने वाले राजनीतिज्ञों में जैक्सन का प्रमुख स्थान था।** उसके और अन्य राजनीतिज्ञों के प्रयत्नों के चलते अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दलों—डेमोक्रेटिक दल और ह्विग दल का उदय हो चुका था। दूसरी तरफ, 1828 ई. के राष्ट्रपति के चुनाव के पहले ही, रिपब्लिकन पार्टी दो गुटों—**राष्ट्रीय गणतन्त्रवादी** (National Republicans) और **प्रजातन्त्रात्मक गणतन्त्रवादी** (Democratic Republicans)—में विभाजित हो चुकी थी। 1828 ई. के राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में जैक्सन ने अपने प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी और राष्ट्रीय गणतन्त्रवादी गुट के उम्मीदवार जॉन एडन्स को पराजित कर दिया। इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार सच्चे अर्थों में जनता का एक प्रतिनिधि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुआ। राष्ट्रपति के पद पर वह व्यक्ति बैठा, जिससे अमेरिकी जनता काफी आशाएं रखती थी। जनता को यह लगने लगा था कि उनकी योजनाओं, कार्यक्रमों और महत्वाकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का उचित समय आ गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था का लोकतन्त्रीकरण

राष्ट्रपति जैक्सन ने अपना ध्यान सबसे पहले 'प्रशासनिक संस्थाओं से जुड़े संगठनों' पर केन्द्रित किया। वह जानता था कि संघीय सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन संघीय अधिकारियों के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक संगठनों को चुस्त-दुरुस्त करके, उन्हें सरकार के प्रति जवाबदेय बनाया जाए। **जैक्सन ने अपना ध्यान इस दिशा में इसलिए भी केन्द्रित किया, क्योंकि इस समय प्रशासन में अयोग्य और वृद्ध अधिकारियों के चलते अक्रियाशीलता और अक्षमता की स्थिति विद्यमान हो चली थी।** महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर मुख्यतः अभिजात्यवर्गीय लोगों की ही नियुक्ति होती थी। उनकी सामन्ती मानसिकता का स्पष्ट प्रभाव प्रशासनिक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल रूप में पड़ता था। अतः जैक्सन ने यह अनुभव किया कि प्रशासन से सम्बन्धित पदों पर योग्य और सामान्य नागरिकों की नियुक्ति की जाए। इस प्रयत्न से ही प्रशासनिक व्यवस्था में लोकतन्त्र की अवधारणा को स्थापित किया जा सकता है।

जैक्सन का स्पष्ट मत था कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए किसी विशिष्ट योग्यता की अनिवार्यता, सामान्य नागरिकों को इन पदों पर आसीन होने से रोकने का एक उपक्रम मात्र है। दूसरे, प्रशासनिक

अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवावधि इतनी अधिक न हो कि वे अपने कार्य में उदासीनता और एकरूपता का अनुभव करने लगें। इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रशासनिक कार्यक्षमता पर पड़ता है। इसके अलावा, राष्ट्रपति ने कार्यालयों में 'रोटेशन की प्रथा' भी आरम्भ की, ताकि कोई एक अधिकारी किसी एक ही पद विशेष पर अधिक समय तक अपनी लालफीताशाही न चला सके।

जैक्सन ने प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार के लिए जो प्रयत्न किए, वे उस समय के अनुसार बहुत प्रगतिशील थे। परन्तु वह भी इन सुधारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करते समय अपनी 'दलीय सीमा' से ऊपर न उठ सका। उसकी पार्टी के लोगों ने यह आशा की थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद जैक्सन प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों की ही नियुक्ति करेगा। उनकी यह आशा निराधार नहीं थी और इस महत्वपूर्ण मामले में जैक्सन ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों का ही अनुसरण किया। उसने उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया जिनकी निष्ठा उसके प्रति संदिग्ध थी। तत्पश्चात् उसने इन पदों पर अपने निष्ठावान लोगों की नियुक्ति की। **इस प्रकार, उसने कार्य के द्वारा यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि संघीय सरकार से सम्बन्धित पदों पर उन्हीं लोगों को नियुक्त करना चाहिए, जिनकी निष्ठा 'सत्तारूढ़ दल' के प्रति असंदिग्ध हो।** यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से भले ही लाभप्रद हो, परन्तु प्रशासनिक दृष्टि से इसके परिणाम हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। ऐसी किसी भी नीति को अपनाने से प्रशासन में अक्रियाशीलता, राजनीतिक गुटबाजी और अयोग्यता का बोलबाला हो जाता है।

यहां यह तथ्य ध्यान में रखना होगा कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया, उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। इनमें से कई ऐसे भी अधिकारी थे, जिनकी निष्ठा सरकार के प्रति संदिग्ध थी। अतः अपनी नीतियों के सुचारु क्रियान्वयन के लिए जैक्सन को यह प्रतीत हुआ कि ऐसे अवांछित अधिकारियों से मुक्ति पाना ही लाभप्रद है। कुल मिलाकर, प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त सांगठनिक बुराइयों को दूर करने के लिए जैक्सन ने जो प्रयत्न किए, वे पर्याप्त नहीं थे। इस क्षेत्र में अभी भी सुधार की बहुत अधिक सम्भावना थी।

आर्थिक स्वार्थों और निष्फलीकरण (Nullification) का प्रश्न

जैसा कि ऊपर ही बताया जा चुका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के आर्थिक स्वार्थ और आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न प्रकार की थीं। जहां उत्तरी राज्यों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया गति पकड़ चुकी थी, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी राज्य अभी भी कृषि अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर थे। उत्तरी राज्यों के उद्योगपति यह चाहते थे कि संघीय सरकार उनके आर्थिक हितों की यूरोपीय प्रतिस्पर्द्धा से रक्षा करे और उनके उत्पादों को संरक्षण प्रदान करे। **सरकार ने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, बाहर से आयातित वस्तुओं पर 'प्रशुल्क दर या तटकर' में वृद्धि कर दी।** यह वृद्धि इसलिए की गई थी कि बाहर की वस्तुएं, अमेरिका में आकर महंगी हो जाएं और अमेरिकी लोग बाध्य होकर अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग करें। इस प्रकार 'उत्तरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था' के लिए तो 'संरक्षण की नीति' लाभप्रद सिद्ध हुई, लेकिन दक्षिणी राज्यों को इस व्यवस्था से हानि उठानी पड़ी। वस्तुतः दक्षिणी राज्य 'कृषि अर्थव्यवस्था' पर निर्भर थे और आवश्यक वस्तुओं के लिए उन्हें आयातित मालों पर निर्भर रहना पड़ता था, परन्तु प्रशुल्क दर में वृद्धि के चलते, अब उन्हें आयातित माल को खरीदने में ज्यादा धन व्यय करना पड़ता था। अतः प्रशुल्क दर या तटकर में वृद्धि, दक्षिणी राज्यों के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही थी। अतः उन्होंने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संघीय सरकार से अपील की, परन्तु यह मामला **'निष्फलीकरण के प्रश्न'** पर आकर उलझ गया। इस मामले में दक्षिणी राज्यों ने पश्चिमी राज्यों का सहयोग भी प्राप्त करने का सफल प्रयत्न किया।

'निष्फलीकरण के सिद्धान्त' के समर्थकों का सीधा तात्पर्य यह था कि यदि संघीय सरकार कोई कानून निर्मित करती है, तो यह कानून राज्यों की इच्छा से ही मूर्त रूप ग्रहण कर सकता है। यदि राज्यों को यह लगे कि कानून उनके हितों के प्रतिकूल है तो इस परिस्थिति में उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वे किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर दें। **इसका सीधा तात्पर्य यह था कि अब 'सम्प्रभुता' राज्यों में निहित होगी, न कि संघ में।** लेकिन ऐसी कोई भी नीति 'संघ की एकता और सम्प्रभुता' के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी, अतः यह प्रश्न घोर विवादों को जन्म देने लगा।

इस सिद्धान्त का प्रमुख पैरोकार, दक्षिण केरोलिना का प्रतिनिधि हेन था, जबकि संघीय सम्प्रभुता का प्रमुख समर्थक मैसाचूसेट्स का प्रतिनिधि वेबस्टर था। इन दोनों व्यक्तियों के मध्य इस प्रश्न को लेकर काफी वाद-विवाद हुए। इस विवाद ने एक-के-बाद एक कई संवैधानिक समस्याओं को जन्म देना प्रारम्भ कर दिया।

इस सिद्धान्त के समर्थकों ने संघ से अलग होने की धमकी देना आरम्भ कर दिया, जबकि इसके विरोधियों ने इसे 'राष्ट्रीय एकता और अखण्डता पर हमला' की संज्ञा देना शुरू कर दिया।

जहां तक राष्ट्रपति जैक्सन का प्रश्न था, तो वह आरम्भ से ही इस समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान ढूंढना चाहता था, परन्तु यह समाधान, **'संघ की एकता और अखण्डता'** की कीमत के आधार पर नहीं होना चाहिए था। उसने इस मत का समर्थन किया कि संघीय सरकार के क्रियाकलाप सीमित होने चाहिए। वह चाहता था कि आन्तरिक सुधारों का दायित्व सम्बन्धित सरकारों को सौंप देना चाहिए। वह प्रशुल्क दरों को घटाने के पक्ष में भी था। अतः उसकी पहल पर कांग्रेस में जुलाई 1832 ई. में एक नया तटकर अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा तटकरों की जिन दरों का निर्धारण किया गया, वे 1828 ई. की तुलना में कम थीं, परन्तु दक्षिणी राज्यों की दृष्टि में तटकरों में यह कमी, अभी भी अपर्याप्त ही थी। वे इसमें और कमी चाहते थे, परन्तु ऐसा होना सम्भव न जानकर उन्होंने अपना संघर्ष तेज कर दिया।

दक्षिण केरोलिना के गवर्नर हेमिल्टन की पहल पर, निष्फलीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए 19 नवम्बर, 1832 ई. को कोलम्बिया में एक राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन किया गया। **इस सम्मेलन में 1828 ई. और 1832 ई. के तटकर कानूनों को अस्वीकृत कर दिया गया।** संघीय सरकार को यह चेतावनी भी दी गई कि यदि उन पर सख्ती की गई तो इसका परिणाम संघ के विघटन के रूप में सामने आ सकता है। इस सम्मेलन के बाद, दक्षिण केरोलिना राज्य ने सम्भावित संघर्ष के लिए सशस्त्र तैयारी भी आरम्भ कर दी।

अब राष्ट्रपति जैक्सन के समक्ष एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, क्योंकि 'निष्फलीकरण की योजना' फरवरी 1833 ई. से लागू होनी थी। अब यदि संघीय सरकार सख्ती न करती तो यह सम्भव था कि दक्षिण केरोलिना राज्य संघ से पृथक् हो सकता था। यह परिस्थिति और उदाहरण संघ के लिए घातक सिद्ध होता। जैक्सन के पक्ष में सकारात्मक बात यह थी कि इस प्रश्न पर, केरोलिना राज्य लगभग अकेला पड़ चुका था और यहां तक कि दक्षिणी राज्य भी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। दूसरे, जनभावनाएं अभी भी इस बात पर केन्द्रित थीं कि किसी भी प्रकार से संघ की एकता अक्षुण्ण बनी रहे। **अतः इन भावानाओं और परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए जैक्सन ने सैन्य तैयारियां आरम्भ कर दीं।** उसने मेजर जनरल विनफील्ड को दक्षिण केरोलिना के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व सौंपा। इसके अलावा, राष्ट्रपति ने अपने कूटनीतिक प्रयत्नों को तेज करते हुए, 4 दिसम्बर, 1832 ई. को कांग्रेस में घोषणा की कि संघीय सरकार तटकरों या प्रशुल्क दरों में कमी करने की दिशा में यथेष्ट प्रयत्न करेगी। तत्पश्चात् 10 दिसम्बर को उसने अपने विदेश सचिव एडवर्ड लिविंग्सटन द्वारा लिखा गया एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा-पत्र में संघ की एकता, अक्षुण्णता और सम्प्रभुता पर बल देते हुए यह कहा गया कि **'निष्फलीकरण का सिद्धान्त'** संघीय हितों के विरुद्ध है। जो राज्य ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे वस्तुतः देशद्रोह कर रहे हैं और ऐसी किसी भी परिस्थिति का सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। स्पष्टतः इसका संकेत दक्षिण केरोलिना की ओर था।

इसी बीच, दक्षिण केरोलिना के गवर्नर के पद पर राबर्ट हेन की नियुक्ति हुई। उसने अपने समर्थन हेतु एक सभा का आयोजन किया, परन्तु इस सम्मेलन में जो आम राय बनी, वह 'निष्फलीकरण के सिद्धान्त' के विरुद्ध थी। वस्तुतः अब इस प्रश्न पर केरोलिना राज्य अलग-थलग पड़ चुका था। **अब दोनों पक्षों में एक बीच का रास्ता अपनाने की बात होने लगी।** विशेषकर हेनरी क्ले के प्रयत्नों से एक समझौतावादी तटकर प्रस्ताव रखा गया। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जिन वस्तुओं पर 20 प्रतिशत से अधिक आयात कर है, उन्हें 1842 ई. तक धीरे-धीरे घटाकर, 1816 ई. के आयात कर के स्तर तक लाया जाएगा। 1833 ई. में यह 'समझौतावादी तटकर प्रस्ताव' और 'सैन्य विधेयक' सम्बन्धी एक अन्य प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया। इसमें से प्रथम व्यवस्था को तो दक्षिण केरोलिना राज्य ने स्वीकार कर लिया, परन्तु अपने सम्मान की रक्षा का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने दूसरा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया।

बैंकिंग और अर्थव्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं

राष्ट्रपति जैक्सन के दूसरे कार्यकाल की सबसे अहम समस्या आर्थिक और विशेषतः बैंकिंग व्यवस्था से सम्बन्धित थी। इस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में 'राष्ट्रीय बैंक' कार्यरत था। यह बैंक 1791 ई. में स्थापित **'बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स'** का सुधरा और विस्तृत रूप था। जैक्सन के कार्यकाल के समय में इस बैंक का अध्यक्ष निकोलस बिडाल था। वह अपने बैंक को उस चरम स्थिति तक ले जाना चाहता था, जहां बैंक **'संघ की आर्थिक नीतियों को निर्धारित और निर्देशित'** करे।

वह चाहता था कि 'संघ' की आर्थिक नीतियों पर बैंक का कड़ा नियन्त्रण स्थापित हो। निश्चित ही उसका यह मत, संघीय सम्प्रभुता पर किया गया आर्थिक आक्रमण का प्रयास था और ऐसे किसी भी प्रयास को स्वीकार करने के पक्ष में जैक्सन नहीं था।

राष्ट्रीय बैंक की नीतियों के चलते दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में आर्थिक असन्तोष बढ़ता जा रहा था। इस बैंक ने राज्यों के बैंकों के द्वारा ऋण जारी करने और अन्य आर्थिक गतिविधियों को अत्यन्त सीमित कर दिया था। अतः इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय बैंक पर यह आरोप लगाया कि बैंक, केवल उत्तरी और पूर्वी राज्यों के पूंजीपतियों के हितों का पोषण कर रहा है और आम जनता के प्रति अपने कर्तव्यों से पूरी तरह उदासीन रहा है। इसके अलावा, बैंक पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह कृषकों के हितों के विरुद्ध कार्य रह रहा है। ये सभी आरोप, सच्चाई के निकट थे। **इस बैंक में सर्वाधिक पूंजी उत्तरी और पूर्वी राज्यों के पूंजीपतियों की लगी हुई थी।** स्पष्टतः लाभ में सबसे अधिक हिस्सा भी उन्हीं पूंजीपतियों का था। जहां तक संघीय सरकार का प्रश्न है तो बैंक में उसका शेयर नाममात्र का था। अतः वह बैंक को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, संघ की मुद्रा प्रणाली और आर्थिक साख पर भी बैंक का पूरा नियन्त्रण स्थापित था। कुल मिलाकर, आर्थिक मामलों में राष्ट्रीय बैंक, संघीय सरकार से कहीं अधिक शक्ति रखता था और इस शक्ति का उपयोग पूंजीपति वर्ग के विकास में करता था, न कि जनता के विकास में।

राष्ट्रपति जैक्सन आरम्भ से ही राष्ट्रीय बैंक की नीतियों, महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं के विरुद्ध रहा था। उसने बैंक की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को लोकतन्त्र के लिए घातक बताया। उसका यह मत था कि बैंक की नीतियों का उद्देश्य संघ और उसकी जनता के आर्थिक हितों को सुरक्षित और संवर्द्धित करने का होना चाहिए। इतना ही नहीं वह चाहता था कि बैंक पर संघीय सरकार का प्रभावी नियन्त्रण स्थापित हो और उसके कार्य और अधिकार क्षेत्र को सीमित कर देना चाहिए।

जैक्सन के उपर्युक्त विचार निश्चित ही बैंक के हितों के प्रतिकूल थे। अतः बैंक के अध्यक्ष बिडाल ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए, जैक्सन का विरोध करना आरम्भ कर दिया। बिडाल के व्यक्तित्व में अभिजात्यवर्गीय श्रेष्ठता की भावना कूट-कूट कर भरी थी और वह आम नागरिकों के हितों के प्रति पूर्णतः उदासीन था। **वह स्वयं बहुत महत्वाकांक्षी था और यह चाहता था कि संघ की आर्थिक गतिविधियों के मामलों में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।** अपनी इस महत्वाकांक्षा के चलते, वह कई बार अपने और बैंक के अधिकार-क्षेत्रों का उल्लंघन भी कर बैठता था। वह अपने अनुचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तरह-तरह के अनुचित हथकण्डे भी अपनाता रहता था। यहां तक कि कांग्रेस के सदस्यों, महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, प्रेस मीडिया के महत्वपूर्ण लोगों, आदि को बड़ी मात्रा में धनराशि प्रदान करता था। ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये लोग बैंक के हितों की रक्षा के लिए लड़ सकें। उसके शक्तिशाली समर्थकों में से सबसे प्रभावशाली नाम 'क्ले' का था।

क्ले की सलाह पर ही, बिडाल ने राष्ट्रीय बैंक की कार्यावधि में नवीनीकरण और विस्तार के लिए 1832 ई. में ही आवेदन कर दिया। हालांकि अभी इसके लिए 4 वर्षों का समय शेष था। चूंकि कांग्रेस में बैंक के समर्थकों की कोई कमी नहीं थी और वे पर्याप्त रूप से प्रभावशाली भी थे। अतः कांग्रेस ने बैंक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। अब राष्ट्रपति जैक्सन ने निर्णायक कदम उठाते हुए, इस प्रस्ताव पर अपने 'वीटो' शक्ति का प्रयोग कर दिया। अब कांग्रेस और राष्ट्रपति आमने-सामने थे। दूसरी ओर, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के बीच भी इस प्रश्न पर मतभेद विद्यमान थे। **वस्तुतः जैक्सन का मानना था कि कांग्रेस, न्यायालय और राष्ट्रपति तीनों लोकतन्त्र के तीन आधार स्तम्भ हैं** और उन्हें एक-दूसरे के प्रभाव और नियन्त्रण से मुक्त रहना चाहिए, परन्तु जहां तक बैंक से सम्बन्धित मामला था, तो जैक्सन इसमें न तो न्यायालय और न ही कांग्रेस का कोई हस्तक्षेप स्वीकार करने को तैयार था। वह मानता था कि संघीय सरकार की जवाबदेयिता, आम जनता के प्रति है और वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को उन्हीं के हितों के अनुरूप संचालित करेगी। अब यह प्रश्न गम्भीर रूप ग्रहण कर चुका था और यह स्पष्ट था कि इसका सीधा प्रभाव 1832 ई. के राष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ेगा।

इस चुनाव में जैक्सन, पुनः एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर पद निर्वाचित हुआ। अतः जैक्सन को यह प्रतीत हुआ कि जनता यह चाहती है कि राष्ट्रीय बैंक पर संघीय सरकार का कड़ा

नियन्त्रण हो। **अतः उसने निर्णायक कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय बैंक में जमा सरकारी पूंजी को हटाने का आदेश दे दिया।** इस धन को प्रान्तीय बैंकों में जमा करवाने की व्यवस्था की गई। जैक्सन का यह कदम अतिवाद का शिकार था। परिणामतः कांग्रेस ही नहीं अपितु उसके भी कुछ समर्थक इस कदम को त्रुटिपूर्ण मानने लगे। सीनेट ने उसके इस निर्णय का तीव्र विरोध भी किया, परन्तु यह विरोध अप्रभावी सिद्ध हुआ। राष्ट्रीय बैंक के विरुद्ध, राष्ट्रपति जैक्सन की विजय हुई। हालांकि 1836 ई. में इस बैंक को नवीनीकरण प्राप्त हुआ, परन्तु वह 'स्टेट चार्टर' के रूप में ही था। निश्चय ही इसके परिणाम साधारण नहीं होने वाले थे।

परिणाम : आर्थिक मन्दी का प्रसार

राष्ट्रपति जैक्सन के 'राष्ट्रीय बैंक' के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय का सीधा लाभ राज्यों की छोटी बैंकिंग संस्थाओं ने उठाया। उन्होंने बड़ी संख्या में पत्र-मुद्रा जारी की, जिसके परिणामस्वरूप देश में मुद्रा-स्फीति और अवमूल्यन की समस्या सर्वव्यापी हो गई। सरकार के राजस्व में, मुद्रा प्रसार के कारण, जबर्दस्त वृद्धि हुई। **संघीय सरकार ने अपने सभी सार्वजनिक ऋणों को चुका दिया।** इसके बाद भी सरकार के पास काफी धन बचा रहा, परन्तु यह एक अस्थायी उत्साह की लहर थी।

जैक्सन की इस नीति का असली दुष्परिणाम 1837 ई. के आरम्भ में सामने आया। इस वर्ष कई बैंकें दिवालियेपन का शिकार हो गईं। उपजों की कीमतें गिर गईं। मुद्रा का प्रसार अपने तीव्र स्तर पर विद्यमान था। **परिणामतः देश में घोर आर्थिक मन्दी का दौर आरम्भ हो गया।** यहां तक कि संघीय सरकार ने यह नियम बना दिया कि सार्वजनिक भूमि का क्रय, स्वर्ण या रजत मुद्रा में ही हो सकता है न कि पत्र-मुद्रा में। यह निर्णय स्वयं में इस बात का सूचक था कि सरकार की राष्ट्रीय बैंक के प्रति नीति त्रुटिपूर्ण थी।

जैक्सन की रेड-इण्डियन्स के प्रति नीति—राष्ट्रपति जैक्सन की रेड-इण्डियनों के प्रति नीति रंगभेद पर आधारित थी। वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहता था, जिसमें रेड-इण्डियन्स उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध हों। **वह चाहता था कि इन्हें मिसीसिपी के पश्चिमी भागों में केन्द्रित कर दिया जाए।** ताकि श्वेत लोग अपनी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को मूर्त रूप दे सकें। इस प्रश्न पर जैक्सन और सर्वोच्च न्यायालय के बीच खींचातानी भी हुई, परन्तु राष्ट्रपति अपनी नीति पर टिका रहा।

वेस्टइण्डीज में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न—वेस्टइण्डीज ब्रिटेन का औपनिवेशिक क्षेत्र था और वहां के व्यापार पर उसका पूरा नियन्त्रण था। वेस्टइण्डीज के बन्दरगाह, अमेरिकी व्यापार के लिए बन्द थे। हालांकि इस स्थिति में परिवर्तन के लिए कई राष्ट्रपतियों ने प्रयत्न किए थे, तथापि उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 1830 **ई. में कांग्रेस ने जैक्सन को इस बात के लिए अधिकृत किया कि वह इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ब्रिटेन से रियायतें प्राप्त करने के लिए उचित प्रयत्न करे।** जैक्सन ने ब्रिटेन से विनम्र स्वर में अपील की और इसका परिणाम यह निकला कि ब्रिटेन ने वेस्टइण्डीज से व्यापार के लिए, अमेरिका को कुछ महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान कर दीं।

न्यायपालिका क्षेत्र में हस्तक्षेप—जैक्सन के राष्ट्रपतित्व काल में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय और संघीय सरकार में वाद-विवाद हुए। जैक्सन के नेतृत्व में जो लोकतन्त्र की भावना बह रही थी, उससे न्यायिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रह सकता था। वस्तुतः न्यायिक क्षेत्र में भी अभिजात्यवर्गीय श्रेष्ठता की भावना विद्यमान थी। न्यायाधीश लम्बे समय तक अपने पदों पर कार्यरत रहते थे और कई बार ऐसे त्रुटिपूर्ण निर्णय देते थे, जो जनता के हितों के प्रतिकूल रहते थे। उनकी चयन प्रणाली पर भी जनता का कोई नियन्त्रण नहीं था। अतः जैक्सन ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए यह व्यवस्था की कि न्यायाधीशों के चुनाव में जनता की भी प्रत्यक्ष भागीदारी हो। न्यायाधीश एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त हों और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों पर जनता की स्वीकृति को आवश्यक बनाया गया। **इस प्रकार, जैक्सन के लोकतन्त्रीकरण का प्रक्रिया का प्रभाव न्यायिक क्षेत्र पर भी पड़ा।**